प्रकाशन का 42 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 42 अंक – 34 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 28 – 4 सितम्बर 2017 मूल्य पांच रूपए

केन्द्रिय मन्त्रीमण्डल के विस्तार के बाद और असपष्ट हुआ भाजपा में प्रदेश नेतृत्व का प्रश्न

शिमला/शैल। हिमाचल में भाजपा किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? यदि प्रदेश में भाजपा को बहुमत मिल जाता है तो अगला मुख्यमन्त्री कौन होगा? प्रदेश में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिये क्या यहां पर उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कुछ कांग्रेस नेताओं को कांग्रेस से तोड़कर भाजपा में शामिल करके उन्हें टिकट दिया जायेगा? यह कुछ सवाल लम्बे अरसे से प्रदेश के राजनीतिक प्रशासनिक हल्कों में चर्चा का विषय बने हुए है। भाजपा के अगामी प्रदेश नेतृत्व के नाम पर करीब आधा दर्जन नेताओं के नाम चर्चा में चल रहे हैं और इसी के साथ जैसे – जैसे यह नामों की चर्चा बढ़ती रही है। उसी अनुपात में हाईकमान की ओर से यह आता रहा कि चुनावों से पहले किसी को भी नेता घोषित नही किया जायेगा। प्रदेश के चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़े जायेंगे लेकिन यहां प्रदेश मे भाजपा व्यवहारिक दृष्टि से धूमल और नड्डा दो खेमों में बंटी हुई है। यह खेमेबाजी इतनी दूर तक निकल चुकी है कि इसको बांटना शायद हाईकमान के लिये भी आसान नही रह गया है। क्योंकि संयोगवंश धूमल के दोनों कार्यकाल में जिन लोगों ने धूमल की कार्यशैली का विरोध किया था और अन्ततः हिमाचल लोकहित पार्टी बनाकर भाजपा से बाहर चले गये थे लगभग वह सब लोग नड्डा के माध्यम से पार्टी में वापिस आ गये है। नड्डा केन्द्रिय चुनाव कमेटी के भी सदस्य है। इससे यहां तक प्रचारित हो गया कि हाईकमान नड्डा को केन्द्रिय मन्त्रीमण्डल से हटाकर हिमाचल भेज रही है। नड्डा के स्थान पर हिमाचल से अनुराग ठाकुर को राज्य मन्त्री बनाये जाने का भी प्रचार हो गया लेकिन अब केन्द्रिय मन्त्रीमण्डल का जो विस्तार सामने आया है उसमें न तो अनुराग को बनाया गया और न ही नड्डा को हटाया गया है। इससे इसी धारणा को बल मिलता है कि शायद अभी नड्डा को हिमाचल नही भेजा जा रहा है। इस प्रसंग में यह भी स्मरणीय है कि पिछले दिनों बिलासपुर में एम्ज खोले जाने को लेकर नड्डा और अनुराग में जो बहस छिड़ गयी थी और उसमें अनुराग ने यहां तक कह दिया था कि बिलासपुर में एम्ज खोलने के लिये नड्डा का कोई योगदान नही है। अब इस एम्ज के मामले में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब हर्ष वर्धन स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय अरूण जेटली ने यह घोषणा की थी लेकिन नड्डा के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद इस दिशा में केन्द्र की ओर से कोई सूचना ही नही मिली है जबकि प्रदेश सरकार ने इस संबध में सारी जिम्मेदारीयां पूरी कर दी है। कौल सिंह के इस कथन से नड्डा की स्थिति और कमजोर हुई है।

इस परिदृश्य में पूरी वस्तुस्थिति का आंकलन करने पर यह उभरता है कि अभी प्रदेश नेतृत्व के प्रश्न पर हाईकमान में भी कोई स्पष्टता नही है। अभी नोटबंदी के परिणामो को लेकर विपक्ष ने जिस ढंग से सरकार को घेरा है उससे सरकार की छवि पर कुछ प्रश्न चिन्ह अवश्य लगे हैं। इसी के साथ सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम के प्रकरण में जिस तरह से हिंसा के लिये अमितशाह और सुब्रहमण्यम स्वामी ने अदालत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और भाजपा के ही सांसद साक्षी महाराज ने तो इनसे भी एक कदम आगे जाकर यह कह

शेष पृष्ठ 8 पर.....

सोशल मीडिया में वायरल हुई भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची

कांग्रेस नेता जी.एस.बाली और करनेश जंग टिकट पाने वालो में शामिल

शिमला/शैल। कांग्रेस के करीब आधा दर्जन नेताओं के नाम भाजपा में शामिल होने वालों के रूप में काफी अरसे से चर्चा में चल रहे हैं। इनमें कई मन्त्रीयों तक के नाम भी खबरों में रहे हैं लेकिन इन खबरों का खण्डन न तो इन नेताओं ने कभी किया और न ही भाजपा की ओर से कोई खण्डन आया बल्कि भाजपा और कांग्रेस दोनों का ही नेतृत्व यह दावा करता रहा है कि एक दूसरे के लोग उनके संपर्क में है। अब भाजपा की ओर से विधान सभा चुनावों के लिये उम्मीदवारों की एक सूची सोशल मीडिया में वायरल हुई है।

इस सूची के मुताबिक भाजपा की केन्द्रिय चुनाव कमेटी की बैठक 28 अगस्त हो हुई थी। इस बैठक में हिमाचल विधानसभा के 31 विधानसभा क्षेत्रों के लिये उम्मीदवारों का चयन फाईनल हुआ है। इस बैठक में हुए फैसले की सूचना 29अगस्त को शाम को चयन समिति के सदस्य जेपी नड्डा द्वारा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती को भेजी गयी है। इसमें कहा गया है कि इस सूची को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितशाह अपने हिमाचल दौरे के दौरान सार्वजनिक करेंगे । इस सूची में कांगड़ा के नगरोटा से कांग्रेस नेता परिवहन मन्त्री जी एस बाली और पांवटा साहिब से करनेश जंग नाम पाने वालों के तौर पर शामिल है। सोशल मीडिया में वायरल हुई यह सूची कितनी प्रमाणिक है इसका पता तो आने वाले समय में ही लगेगा। लेकिन इसमें यह हुआ है कि जैसे ही इस सूची के वायरल होने की जानकारी पार्टी अध्यक्ष सत्ती को हुई उन्होने पत्र लिखकर अपने आईटी सैल को इसके लीक होने की जांच करने के निर्देश जारी कर दिये है।

इस सूची के मुताबिक नड्डा के गृह विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर से त्रिलोक जम्वाल को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह हमीरपुर से प्रेम कुमार धूमल के स्थान पर उनके छोटे पुत्र अरूण धूमल को टिकट दिया गया है। यदि यह सूची सही है तो इसके मुताबिक नड्डा और धूमल दोनो ही नेतृत्व से बाहर हो जाते है।

यह है वायरल हुई सूची

--------- Forwarded message ---------
From: JP Nadda<jpnadda@gmail.com>
Date: Tue, Aug 29, 2017 at 6:52 PM
Subject: Re: Confidential Notice Regarding Candidates
To: Satpal Satti ji<presidentbjphp@gmail.com>
Cc: Gehlot ji<mptcgehlot@gmail.com>

On Tue, Aug 29, 2017 at 6:49 PM, JP Nadda <jpnadda@gmail.com> wrote:
Satpal Satti Ji,

Below is the 1st list of the candidates chosen by the central election committee for the ensuing Legislative Assembly elections. Amit Shah ji will announce the candidates when he visits Himachal Pradesh in the month of September. It will be released to the press thereafter.

Monday, 28 August 2017

The Central Election Committee of the Bharatiya Janata Party met yesterday under the leadership of Shri Amit Shah.

The meeting was attended by all the members of the Central Election Committee of the BJP. The Committee has decided the following names for the ensuing General Elections to the Legislative Assembly 2017 of Himachal Pradesh.

1st List Of HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY

A. C. NO.	Assembly Constituency Name	Category	Final Candidate
1	Churah	(SC)	Hans Raj
4	Dalhousie	GEN	Manoj Chaddha
6	Nurpur	GEN	Rakesh Pathania
9	Jawali	GEN	Vishal Chouhan
11	Jaswan-Pragpur	GEN	Bikram Thakur
12	Jawalamukhi	GEN	Pavan Rana
14	Sullah	GEN	Vipin Singh Parmar
15	Nagrota	GEN	G S Bali
17	Shahpur	GEN	Karnik Padha
27	Sundernagar	GEN	Rakesh Jamwal
29	Seraj	GEN	Jai Ram Thakur
32	Dharampur	GEN	Narender Attri
33	Mandi	GEN	Praveen Sharma
35	Sarkaghat	GEN	Col Inder Singh
38	Hamirpur	GEN	Arun singh Dhumal
39	Barsar	GEN	Baldev Sharma
40	Nadaun	GEN	Vijay Agnihotri
42	Gagret	GEN	Sushil Kumar Kalia
43	Haroli	GEN	Ram Kumar
44	Una	GEN	SatpalSingh Satti
45	Kutlehar	GEN	Virender Kanwar
46	Jhandutta	(SC)	J R Katwal
47	Ghumarwin	GEN	Mahender Dharmani
48	Bilaspur	GEN	Trilok Jamwal
53	Solan	(SC)	Kumari Sheela
56	Nahan	GEN	Rajiv Bindal
58	Paonta Sahib	GEN	Kirnesh Jung
64	Shimla Rural	GEN	Sunil thakur
65	Jubbal-Kotkhai	GEN	Narinder Bragta
66	Rampur	(SC)	PS Draik
68	Kinnaur	(ST)	Surat Singh negi

शैल समाचार के नियमित पाठक बनने हेतू
विज्ञापन देने के लिये इन नम्बरों पर संपर्क करें
कार्यालय दूरभाष – 0177 – 2805015, मो. 8988587014, मो. 9418069978, मो. 9418020312
ई मेल – shailsamachar@gmail.com, वेबसाईट – www.shailsamachar.co.in
पाठकों की प्रतिक्रियाओं को भी विशेष स्थान दिया जायेगा
– संपादक

सोलन जिले को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले को राष्ट्रीय स्तर पर 'स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार' प्रदान किया गया है। केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर से नई दिल्ली में सोलन के उपायुक्त राकेश कंवर ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार 'स्वच्छ भारत – स्वच्छ विद्यालय' प्रयास के अंतर्गत प्रदान दिया गया।

राकेश कंवर ने नई दिल्ली से इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सोलन जिले को विद्यालय स्वच्छता के लिए देशभर के 11 सर्वश्रेष्ठ जिलों में चुना गया था। इनमें सोलन देश में दूसरे स्थान पर रहा। उन्होंने कहा कि सोलन जिले को आज राष्ट्रीय स्तर पर दो पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें एक पुरस्कार सोलन जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले के लिए तथा दूसरा पुरस्कार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भाटियां, नालागढ़ को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार वर्ष 2016 – 17 के लिए दिया गया।

उपायुक्त ने कहा कि इन पुरस्कारों के लिए देशभर के 3.5 लाख से अधिक विद्यालयों ने ऑनलाईन आवेदन किया था। इनमें से 2.68 लाख विद्यालयों ने आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी की। इसके उपरान्त सभी विद्यालयों का जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन किया गया। इस प्रक्रिया के उपरान्त देशभर से 648 विद्यालयों को चुना गया। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के उपरान्त उक्त 648 विद्यालयों का भारत सरकार द्वारा 'थर्ड पार्टी' द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन करवाया गया। इस प्रक्रिया में अन्तिम रूप से देश के 172 विद्यालय चुने गए। उन्होंने कहा कि इन 172 विद्यालयों में सोलन जिला के नालागढ़ उपमण्डल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भाटियां को चुना गया।

उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ भारत – स्वच्छ विद्यालय प्रयास के तहत् सोलन जिले को पुरस्कार मिलने पर सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, अध्यापकों तथा छात्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के पुरस्कार निश्चित रूप से सभी को और बेहतर करने की दिशा में प्रेरणा देते हैं। उन्होंने आशा जताई कि सोलन जिला भविष्य में भी स्वच्छता की दिशा में अग्रणी रहेगा। इन पुरस्कारों के लिए विद्यालयों में पेयजल, शौचालय, साबुन से हाथ धोना जैसे विभिन्न कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया गया। केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार विद्यालयों में स्वच्छता एवं साफ – सफाई जैसे क्रियाकलापों को पहचान दिलाने, छात्रों को इस दिशा में प्रोत्साहित करने एवं उत्कृष्ट बनाने के लिए आरम्भ किए गए हैं।

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने निपटाए 12780 मामले

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि 28 फरवरी, 2015 से लेकर अभी तक कुल 25473 प्राप्त मामलों में से 12780 मामलों का निपटारा किया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से प्राप्त 6440 मामलों में से 1223 मामले निपटाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 282 अवमानना याचिकाएं, 16 समीक्षा याचिकाओं व 21 पूर्व याचिकाओं सहित 5392 विविध आवेदनों का भी निपटारा इस अवधि के दौरान किया गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने वर्ष 2009 से पूर्व के पुराने लम्बित मामलों का निपटारा डिवीजनल बैंच द्वारा प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्णय लिया है।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
" NOTICE INVITING TENDER"

Sealed item rate tender are hereby invited in form No.6&8 by the Executive Engineer B&R Division,HP.PWD. Sarkaghat HP.on behalf of the Governor of Himachal Pradesh for the following works from the instruction and are also registered contractor of appropriate class enlisted in HP.PWD whose registration stood renewed as peer revised instruction and are also registered dealers under the Himachal Pradesh General sales Tax Act.1968.The important dates of tender are as under:-

The last date and time of receipt of application for tender form 29.09.2017 up to 4.00 P.M.
The last date for sale of tender is up to 03.10.2017 at 4.00PM.
The tender shall be received up to 11:00 AM on 04.10.2017 to be opened on the same day at 11:30 AM. in presence of the intending contractors or their authorized representative who may like to be present. The tender form can be had from this office against cash payment as shown below(Non refundable) during the working hours on 04.10.2017 .The earnest money in the shape of National saving certificate, time deposit account in any post office/bank in HP .duly pledged in favor of the Executive Engineer B&R Division HP.PWD.Sarkaghat must accompany with each tender Conditional & in complete tenders and the tender received without earnest money will be summarily rejected. The offer of tender shall be kept open for 120 days. The Executive Engineer, reserved the right to accept or reject, the tender without assigning any reason.

Sr. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of Form	Time Limit
1.	Construction of Padasala to Ambi via Kalohdhar road Km. 0/0 to 4/200(SH:- Providing and laying metalling and tarring in Km. 0/500 to 1/500)under SCSP.	9,45,309/-	19000/-	350/-	Two Month
2.	Construction of Triphalghat to Badoun,Batehra road in G.P. Nawani Km. 0/0 to 10/0(SH;- Providing and laying tarring in Km. 6/500 to 7/0)under SCSP..	3,50,674/-	7,100/-	350/-	One Month
3.	Construction of link road Tikkari to Mandoli,Khudla via Gehra,Bhadrol Km. 0/0 to 2/500(SH:- Providing and laying soling in Km. 0/700 to 1/200)under SCSP.	1,70,207/-	3,500/-	350/-	One Month.
4.	Construction of accommodation and tolit block for Girls sports hostel at Govt. Sr.Sec.School at Sarkaghat,Distt-Mandi (HP) (SH:- Construction of building portion including W.S. & S.I. septic tank and rain water harvesting tank)(Deposit).	8,47,578/-	17,000/-	350/-	Nine Months.
5.	Improvement of black spot on Dewarwal,Jamanwal,Ban Magoh,Sadwal Km.0/0 to 8/500(SH:- Construction of cement concrete pavement at Km. 0/015 to 0/065 and 0/890 to 0/940)	2,10,706/-	4,300/-	350/-	Two Months.
6.	Improvement of Black spot on Bag Pounta,Bahi ,Kharsal,Bahi road Km. 0/0 to 4/0(SH:- Construction of cement concrete pavement at Km. 0/065 to 0/120 and 2/015 to 2/065).	2,10,706/-	4,300/-	350/-	Two Months
7.	Annual surfacing on Plassi to Lahra road Km. 0/0 to 1/0 and 3/0 to 3/500(SH:- Construction of cement concrete pavement at Km. 0/225 to 0/505) for the year 2017-18 DRRP No. HP0807VR0072.	5,89,867/-	11,800/-	350/-	Two Months.

TERMS AND CONDITONS:-
Following documents should accompany with the application for tenders.
1.Sale tax No.with latest sale tax clearance certificate for tenders:-
2.Valid copy of Registration.
3.Pan No.with latest income tax clearance certificate.
4.EPF registration.
5.Under taking/affidavit regarding possession of required machinery Telegraphic, Fax tender are not acceptable.
6.The tender documents can be received by Registered/insured post which should be received in this office on or before the date of opening the tender by 10:30 AM positively.
7.The tender form and the terms and conditions of the tender can be had from this office between 10:00 AM. To 5:00 PM. On any working day against the payment. The tender documents so sent should invariably to be waxed sealed cover.
8.@ 1% labour cess shall be deducted from each running bill of the contractor.

Adv. No.- 2492/17-18 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
" NOTICE INVITING TENDER"

Sealed item/percentage rate tenders on form 6 & 8 for the following works are invited by the Executive Engineer, Kumarsain Division, HP.PWD, Kumarsain from the experienced contractors enlisted with HPPWD for B&R works so as to reach in this office on or before 28.09.2017 up to 10:30 AM and will be opened on same day at 11:00 AM in the presence of intending contractors or their authorized representatives who may wish to be present.

The application for issue of tender form shall be received on 27.09.2017 up to 1:00 P.M. The tender form shall be issued against cash payment (non refundable) on 27.09.2017 from 1:00 PM to 5:00 PM. The earnest money must accompany with each application in the shape of Time deposit receipt/FDR and the deposit receipt of any post office or any recognized bank in HP duly pledged in the name of undersigned. The contractors who did not deposit the earnest money their tender shall summarily be rejected. The undersigned have the right to reject the tender without assigning any reason.

1. Name of Work: Construction of link road to Bageen Devkanali Km.0/000 to 0/585 (SH: Formation Cutting 5/7 Mtrs wide road in Km.0/000 to 0/585). Estimated Cost: - Rs.9,58,142/- Earnest Money:- Rs.19,200/- Time:- Three Months.

2. Name of Work: - Construction of Gharewati to Lower Tipper road Km. 0/000 to 0/840 (SH:-Formation Cutting 5/7 mtrs wide road in Km.0/135 to 0/840). Estimated Cost: - Rs.8,57,396/- Earnest Money:- Rs.17,200/- Time:- Six Months.

Terms and Conditions: -
1. The contractors shall produce their latest registration/renewal of their registration/latest sale tax clearance certificate/TINNo/PAN Number /E.P.F Registration number/GST Registration Number along with their application.
2. The single/conditional tender will be rejected.
3. The offer shall remain valid up to 90 days.

Adv. No.- 2446/17-18 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
" NOTICE INVITING TENDER"

Sealed item rate tenders are hereby invited by the Executive Engineer, Hamirpur Division HPPWD., Hamirpur in form No. 6 & 8 on behalf of Governor of H.P. for the following works from the contractors of appropriate class enlisted with HP.PWD. The tender shall be opened in the presence of the contractors / firms or their representative who wish to be present.

TIME SHEDULE OF TENDER:-

1. Date and time of receipt of application for tender form:-	26.09..2017 up to 4.00 P.M.
2. Date and time of issue of tender form :-	27.09.2017 up to 4.00 P.M.
3. Date and time of receipt of tenders:-	29.09.2017 up to 10.30 A.M.
4. Date and time of opening of tenders:-	29.09.2017 at 11.00 A.M.

The request for issue of tenders should be on the PRESCRIBED APPLICATION FORM which can be obtained from the office of undersigned and tenders will be issued to only those contractors who qualify the criteria after the scrutiny of application forms by the Committee constituted for this purpose.

Sr. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time Limit	Cost of Form
1.	Restoration of rain damages on Khiah Bhatera via Thalakna Bharnot road Km. 0/0 to 4/885. (SH:- C/O R/Wall at RD. 2/788 to 2/795, 2/797.40 to 2/801 and toe wall at RD. 796.20)	3,50,499/-	7,100/-	Two Months	350/-
2.	Restoration of road damages due to laying of sewerage pipe by I&PH deptt. On Various roads in Nadaun Town (SH:- Providing and fixing crash barrier at Km. 5/800 to 5/847)	3,37,455/-	6,750/-	Two Months	350/-

Terms and condition
1. The earnest money in the shape of National Saving Certificate, Time deposit account in any of the post office in HP / FDR of any Bank duly' pledged in favour of Executive Engineer, Hamirpur Division, HP.PWD. , Hamirpur must be accompanied with the application for receipt of tender form along with cost of form. Tender application received without earnest money will summarily be rejected.
2. The contractors / firms should possess the following documents (photo copy to be attached with application for obtaining the tenders documents):-
(i) Latest enlistment /renewal orders with application for obtaining the tenders documents.
(ii) GST Number issued by the Income Tax Department.
(iii) PAN (Permanent Account Number) issued by the Income Tax Department.
3. The Executive Engineer, Hamirpur Division HPPWD., Hamirpur reserves the right to reject any tender without assigning any reasons(s).
4 The Cess Charges @ 1% will be deducted from the gross amount of work done by the Contractor.
5. A contractor enlisted in a particular class shall be eligible to tender for his own class and one step below.
6. Only one No. tender form will be issued to the eligible contractor.
7. If 29.09.2017 happens to be holiday the tender shall be opened on next working day at 11.00.
8. GST will be dedected as per rates fixed by the Govt..

Adv. No.- 2410/17-18 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
" NOTICE INVITING TENDER"

Sealed item rate tenders are hereby invited by the Executive Engineer, Spiti B&R Division, HP.PWD; Kaza on behalf of the Governor of Himachal Pradesh for the below noted works from eligible Contractors registered in H.P.P.W.D. in appropriate class so as to reach in this office on or before 25-09-2017 up to 3.00 PM. and the same shall be opened on the same day at 3.30 PM., in the presence of the Contractors or their authorized representatives who may be present. The tender forms can be had from this office against cash payment (Non Refundable) on 23-09-2017.

The tender shall accompany with earnest money which should be in the shape of NSC/Time Deposit/Saving Bank account in the Post Office/bank in H.P. duly pledged in the favour of undersigned.

Conditional tenders, telegraphic and tender without earnest money will not be entertained. The Executive Engineer, Spiti B&R Division, HP.PWD; Kaza reserves the right to accept or reject the tenders. The tender shall remain valid for 120 days from the date of opening of the tenders.

Sr.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time
1.	Alternate route to kirnallah via tallung km o/o to 3/870 (Sh-C/O wire crate wall at km 1/210 to 1/240)	351959/-	7200/-	Six Months
2.	C/O link road from tailing todna yensa road (Sh- C/O 3 meter span culvert at km 0/450)	440306/-	8900/-	Six Months
3.	M/T Linkroad from GBKT road to village chicham (Sh- Providing and laying wearing G2 in Km 0/0 to 1/0)	239668/-	4800/-	Six Months
4.	C/O Kaza Langaza road km 0/0 to 14/0 (Sh- improvement of narrow reaches at Km 4/830 to 4/965)	425623/-	8500/-	Six Months

TERMS AND CONDITIONS:-
1. The Contractor/Firm shall have his Sale Tax Number, PAN card & copy of the same be attached with the application.
2. The intending Contractor/Firm Should have attached copy of registration/Renewal.
3. The intending Contractors are requested to see the site of the work before submitting the tender.
4. Tender documents shall be issued to those contractors/Firms who submitted the certificate from Executive Engineer concerned to the effect that he has completed successfully similar nature of works during last three years in respect of tarring work.
5. The Executive Engineer reserves the right to reject/accept any or all the tenders without assigning any reasons.

Adv. No.- 2444/17-18 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक – जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार – ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

आर्थिक विकास में जल विद्युत क्षेत्र की अहम् भूमिका:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार जल विद्युत क्षमता के तीव्र दोहन को उच्च प्राथमिकता दे रही है जो प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा प्रदेश के विभिन्न नदी तटों के जल विद्युत

निर्माताओं व अन्य हितधारकों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सेमीनार की अध्यक्षता कर रहे थे । इस आयोजन को जल विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए एक आवश्यक पहल करार देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल विद्युत क्षमता के दोहन के लिए जल विद्युत नीति में शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत क्षेत्र आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्य सभी क्षेत्र विद्युत की उपलब्धता पर निर्भर हैं। प्रदेश सरकार इस तथ्य से भली-भांति परिचित है तथा जल विद्युत क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है और इससे दूरदराज के क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित होगा तथा प्रदेश के राजस्व में बढ़ौतरी का मुख्य संसाधन होगा।

उन्होंने कहा कि यद्यपि गत वर्षों में जल विद्युत क्षेत्र में गिरावट आई है लेकिन यह कोई चिन्ता का विषय नहीं बल्कि यह प्रकिया का ही हिस्सा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को हर सम्भव सहायता प्रदान करेगी जो प्रदेश की आर्थिकी का एक मुख्य संसाधन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को राज्य के प्रत्येक भाग में विश्वसनीय एवं गुणात्मक विद्युत आपूर्ति करने का गौरव है जहां बहुत पहले शत-प्रतिशत राजस्व गांवों को बिजली की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि केवल यही नहीं, राज्य के उपभोक्ताओं को देश भर में सबसे कम दरों पर बिजली प्रदान की जा रही है।

वीरभद्र ने कहा कि सरकार शेष क्षमता का इस तरीके से दोहन करने को प्राथमिक दे रही है जिससे राज्य को और अधिक राजस्व प्राप्त हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र, दोनों की जल विद्युत विकास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सहभागिता सुनिश्चित बनाने की पहल की गई है। उन्होंने रेखांकित करते हुए कहा कि जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान मुख्य पहलुओं के आंकलन की आवश्यकता तथा निरन्तरता, पर्यावरण के अनुकूल विकास के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन की संभावनाओं की अनुकूलता के अनुरूप परिस्थितियों से निपटने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल विद्युत के उत्पादन जैसे महत्वकांक्षी कार्यक्रम को शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2006 में अलग से अपनी जल विद्युत नीति बनाई है। नीति का निर्माण लोगों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित बनाना तथा पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण सुरक्षा के नाजुक संतुलन को बनाए रखना है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव तरूण श्रीधर ने कहा कि राज्य सरकार ने जल विद्युत क्षेत्र के पुनरूद्धार के लिए प्रभावी कदम उठाने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया है। सरकार ने ऊर्जा उत्पादकों की सुविधा के लिए अनेक प्रोत्साहनों की पेशकश भी की है। उन्होंने ऊर्जा उत्पादकों से इस क्षेत्र के पुनर्जीवन के लिए सरकार को सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया।

केन्द्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष ए.बी. पाण्डेय ने अपने मुख्य भाषण में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृतियों में देरी के मामलों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह एक मुख्य मुद्दा है। आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित बनाने के साथ-साथ परियोजनाएं आंरभ करने के लिये ठोस योजना तथा गहन जांच अन्य महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो जल विद्युत ऊर्जा के लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो, जिसके लिए सम्बन्धित समुदाय को भी आवाज उठानी चाहिए।

एचपीपीसीएल के प्रबन्ध निदेशक देवेश कुमार ने सेमिनार आयोजित करने के उद्देश्य तथा राज्य सरकार द्वारा जल विद्युत क्षेत्र के पुनरुद्धार के किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला।

सुजानपुर में करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हमीरपुर के दो दिवसीय दौरे के दौरान क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने सुजानपुर के लिए 8.68 करोड़ रुपये की मलनिकासी परियोजना का लोकार्पण किया। उन्होंने 12.15 करोड़ रुपये की पटलांधार-कसहीरी महादेव-चमियाणा-डूहक-चबूतरा के लिए उठाऊ पेयजल योजना का भी लोकार्पण किया। इससे क्षेत्र की लगभग 40 हजार जनसंख्या लाभान्वित होगी। उन्होंने 81.87 लाख रुपये की लागत से निर्मित झनियारा-बस्सी उठाऊ पेयजल योजना के संवर्द्धन का भी लोकार्पण किया।

उन्होंने ऊटपुर में 89 लाख रुपये की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन, टौणी देवी के भवानी में 97 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित पुलिस चौकी तथा घऊं- दा-नाला के झनियारा में 55.50 लाख रुपये की लागत से निर्मित पैदल चलने योग्य पुल का भी लोकार्पण किया।

वीरभद्र सिंह ने सुजानपुर में 58 लाख रुपये की लागत से बनने वाले पशु अस्पताल की भी आधारशिला रखी। उन्होंने सुजानपुर में 3.46 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले टाऊन हाल, खैह थलकाना सड़क के पुंग खड पर 2.23 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले पुल तथा उन ऑनसला में 7.55 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले 33 के.वी. विद्युत उप केन्द्र की भी आधारशिला रखी।

2022 तक हिमाचल होगा टीबी मुक्त

शिमला/शैल। क्षयरोग नियंत्रण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है तथा वर्ष 2025 तक राष्ट्र को टीबी मुक्त करने के लक्ष्य से पूर्व प्रदेश में यह लक्ष्य वर्ष 2021-22 तक प्राप्त कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने यह बात टीबी एवं फेफड़ों के रोग की रोकथाम पर अन्तरराष्ट्रीय संघ द्वारा 'प्रशिक्षक बैच के प्रशिक्षण' पर आयोजित टी.बी. एवं तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कही।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है और राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं योजनाएं राष्ट्रीय मानदण्डों के अनरूप कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मानक राष्ट्रीय दर से कहीं बेहतर है तथा प्रदेश अब वैश्विक मानकों को प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2.3 की राष्ट्रीय जन्म दर के मुकाबले प्रदेश में कुल जन्म दर 1.7 है, जबकि 37 की राष्ट्रीय नवजात शिशु मृत्यु दर के मुकाबले प्रदेश में यह दर 28 है। देश में पांच वर्ष की आयु से कम के शिशु की मृत्यु दर 43 है, जबकि प्रदेश में यह दर केवल 33 है।

ठाकुर ने कहा कि चिकित्सा जगत में रोगों का पता लगाने तथा चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक प्रगतियों के बावजूद टीबी विश्व भर में सबसे अधिक घातक व जानलेवा बीमारी है, जिससे हरवर्ष लगभग 14 लाख लोगों की जानें जाती हैं, जिसमें से 4.8 लाख केवल भारत में ही जान गंवाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर वर्ष टीबी के 15 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं तथा लगभग 8 हजार से 9 हजार टीबी रोगी निजी चिकित्सा क्षेत्र में इलाज करवा रहे हैं और यह संख्या भी बहुत अधिक है।

मंत्री ने कहा कि प्रदेश में आरएनटीसीपी कार्यक्रम के तहत टीबी के मामलों का पता लगाने की दर तथा सफल चिकित्सा दर क्रमश: 77 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत है, जबकि देश में यह दर क्रमश: 70 प्रतिशत तथा 85 प्रतिशत है। उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना के अन्तर्गत 2 करोड़ रुपये स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य ने 26 जनवरी, 2017 को टीबी रोगियों के लिए एफडीसी एवं प्रतिदिन खुराक आरम्भ करने में भी प्रथम स्थान हासिल किया, जिसमें 7 हजार से भी ज्यादा रोगियों को प्रतिदिन खुराक प्रदान की जा रही है, ताकि एमडीआर-टीबी रोगियों को पौष्टिक आहार प्रदान किया जा सके।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीबी से मृत्यु में लगभग 38 प्रतिशत मामले तम्बाकू से जुड़े हैं तथा टीबी के मामले धूम्रपान न करने वाले रोगियों के मुकाबले धूम्रपान करने वाले रोगियों में 3 गुणा ज्यादा पाये जाते हैं। राज्य सरकार ने प्रभावी तम्बाकू नियंत्रण के लिए अनेक नए कदम उठाए हैं तथा राज्य में इनको लागू करने के लिए सुदृढ़ प्रणाली मौजूद है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश ने वर्ष 2013 में धूम्रपान मुक्त प्रदेश का दर्जा भी हासिल किया।

संगोष्ठी में हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा तथा चण्डीगढ़ से आए प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

मुख्य सचिव ने किया 'हि.प्र.लोक वित्तीय प्रबन्धन एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम' का शुभारम्भ

शिमला/शैल। मुख्य सचिव वी. सी. फारका ने प्रदेश के सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों (डीडीओ) को आगामी चार वर्षों के दौरान ऑनलाईन सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि शत-प्रतिशत कैशलेस लेन-देन सुनिश्चित बनाया जा सके। उन्होंने आहरण एवं वितरण अधिकारियों की संख्या कम करने पर भी बल दिया जो वर्तमान में प्रदेश में 4400 से अधिक है।

मुख्य सचिव ने यह जानकारी विश्व बैंक वित्त पोषित 'हिमाचल प्रदेश लोक वित्तीय प्रबन्धन एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम' का शुभारम्भ करने के उपरान्त दी। कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व बैंक द्वारा 36 मिलियन डॉलर की सहायता की जाएगी, जबकि 20 प्रतिशत राशि प्रदेश सरकार वहन करेगी। इस प्रकार यह परियोजना 45 मिलियन अमेरिकन डॉलर की होगी और इसे वर्ष 2017 से 2022 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस परियोजना को प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश के विश्व बैंक के साथ बेहतर समन्वय व पूर्व में हासिल बेहतर मानकों के चलते यह संभव हुआ है। उन्होंने विश्व बैंक दल का इस परियोजना को स्वीकृत करने के लिए आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि परियोजना के अन्तर्गत राज्य को वांछित धनराशि प्राप्त करने के लिये लक्ष्यों को हासिल करना होगा तथा लोक वित्त प्रबन्धन के लिए धन राशि के बेहतर प्रबन्धन की आवश्यकता, उपयुक्त ऑडिट और समुचित उपयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में ई-प्रापण प्रणाली लागू की जाएगी, जो पहले ही सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य व लोक निर्माण विभाग में आरम्भ की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या है तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग प्रदेश भर में हिमस्वां को स्तरोन्नत करने व इसके प्रसार के लिए प्रयासरत है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) डा. श्रीकांत बाल्दी ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि परियोजना को विश्व बैंक की तकनीकी सलाह के अनुरूप कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। सभी डीडीओ को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना से लोक वित्त के सही प्रकार से प्रबन्धन में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोक वित्तीय नियम बनाए गए हैं और अब इस कार्यक्रम को सही प्रकार से कार्यान्वित करने के लिये संबद्ध विभागों को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी कोषागारों को पहले ही ऑनलाईन किया जा चुका है।

हिमाचल प्रदेश के प्रधान महालेखाकार कुलवन्त सिंह ने प्रस्तुति के दौरान जानकारी दी वर्तमान में डाटा मैनुअल व इलैक्ट ॉनिक दोनों तरह से प्राप्त किया जा रहा है। इस परियोजना के लागू होने से समस्त कार्य पेपरलैस हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 1946 के बाद के पैंशन का पूरा रिकॉर्ड डिजिटाईजड कर लिया गया है और आगामी पांच वर्षों में सभी प्रकार के बाउचर व रिकार्ड डिजिटाईजड कर दिए जाएंगे।

विश्व बैंक टीम लीडर तरूण माथुर ने विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों व नीतियों के कार्यान्वयन में बेहतर मानक प्राप्त करने के लिए राज्य की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने एनआईसी व सूचना प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विश्वास जताया है और बेहतर कार्य किया है।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आबकारी एवं कराधान, एनआईसी, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा लोक निर्माण विभागों ने इस अवसर पर अपनी-अपनी प्रस्तुतियां दीं।

मुख्य सचिव वित्त डी.डी. शर्मा ने कार्यवाही का संचालन किया तथा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव तरूण कपूर, प्रधान सचिव जगदीश शर्मा, एनआईसी के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक अजय चाहल ने भी इस अवसर पर अपने विचार प्रकट किये।

अनुसूचित जाति उप-योजना में इस वर्ष खर्च होंगे 1435.83 करोड़

शिमला/शैल। निदेशक अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विभाग संदीप भटनागर ने अनुसूचित जाति उप-योजना के तहत विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि प्रदेश में इस वर्ष अनुसूचित जाति उप-योजना के तहत 1435.83 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

भटनागर ने अधिकारियों से कहा कि विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही यह योजनाएं कमजोर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इन योजनाओं का कार्यान्वयन सही समय से पूरा कर लिया जाए और आबंटित बजट को निश्चित समय सीमा के भीतर खर्च किया जाए। उन्होंने विभागाध्यक्षों से कहा कि विभाग द्वारा फील्ड अधिकारियों को जिला स्तर पर आबंटित बजट की सूचना संबंधित उपायुक्तों को भी अवश्य दें, ताकि बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सके।

वन की अग्नि चन्दन की लकड़ी को भी जला देती है अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते है। .....चाणक्य

सम्पादकीय

नोटबंदी का सच

रिर्जव बैंक ऑफइण्डिया ने दावा किया है कि नोटबंदी के तहत बैन किये गये 500 और 1000 के 99% नोट वापिस आ गये हैं केवल 1% पुराने नोट वापिस नही आये हैं। नोटबंदी में 500 और 1000 के नोट बंद किये गये थे और इसके लिये एक तर्क दिया गया था कि बड़े नोटों से काला धन जमा रखने में आसानी होती है। यह भी तर्क दिया गया था कि इससे आंतकी गतिविधियों में कमी आयेगी। नोटबंदी के दौरान जो आम आदमी को असुविधा हुई है उसके कारण उस समय 100 से अधिक लोगों की जान गयी है। यह सच भी सबके सामने है। नोटबंदी के बाद आंतकी हमलों में भी कोई कमी नही आयी है। प्राय: हर दिन कहीं न कहीं कोई वारदात होती ही रही है। नोटबंदी के बाद मंहगाई में भी कोई कमी नहीं आयी है। नोटबंदी के बाद देश के भीतर कितना कालाधन मिला इसको लेकर भी कोई अधिकारिक आंकड़ा आरबीआई की ओर से जारी नही हुआ है बल्कि इसको लेकर वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 16 मई को जो आंकड़े सामने रखे थे अब प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को देश के सामने रखे आंकड़ो में इन्हे आधा कर दिया है। नोटबंदी के बाद नये नोट छापने के लिये आरबीआई ने करीब आठ हजार करोड़ खर्च किये हैं यह दावा भी आरबीआई ने ही किया है।

इस परिदृश्य में यदि नोटबंदी के फैसले का आकंलन किया जाये तो सरकार के अपने ही कृत्य से यह फैसला तर्क की कसौटी पर खरा नही उतरता है क्योंकि नोटबंदी के बाद भी सरकार/आरबीआई 500 और 2000 के नये नोट लेकर सामने आयी है। यदि बड़े मूल्य के नोटों के माध्यम से कालाधन जमा करना आसान होता है तो अब दो हजार मूल्य का नोट आने से तो यह और आसान हो जायेगा। तो क्या माना जाये कि सरकार ने कालेधन वालों को और सुविधा देने के लिये नोटबंदी का कदम उठाया। जाली नोट जिस तरह से पहले छप रहे थे अब भी वैसे ही यह धंधा चला हुआ है। जाली नोटों के कई मामले पकड़े गये हैं। नोटबंदी सरकार का एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी फैसला करार दिया जा रहा था। इन्ही सुधारों की कड़ी में सरकार ने जनधन योजना के तहत जीरो बैलैन्स पर लोगों के खाते खुलवाये। लेकिन आज भी आधे से ज्यादा जीरो बैलैन्स पर ही चल रहे हैं। इनमें कोई ट्रांजैक्शन हो नही रही है क्योंकि इन लोगों के पास बैंक में जमा करवाने लायक पैसा है ही नही बल्कि यह खाते खोलने के लिये जो बैंको का खर्च आया है वह हर आदमी पर एक अतिरिक्त बोझ पड़ा है। इसी के साथ सरकार ने सारी ट्रांजैक्शन डिजिटल करने पर बल दिया है। ई–समाधान की ओर बढ़ने की आवश्यकता की वकालत की जा रही है। लेकिन इस दिशा का कड़वा सच यह है कि आज भी देश में हर स्थान पर 24 X7 निर्बाध बिजली की आपूर्ति नही है। राजधानी नगरों तक में यह सुनिश्चितता नही है। जबकि डिजिटल के लिये निर्बाध बिजली बुनियादी आवश्यकता है। जब बिजली की आपूर्ति निर्बाध नही है तो उसका प्रभाव इन्टरनैट सर्विस पर पड़ना स्वभाविक है। इसी कारण सरकार की संचार सेवाएं अक्सर बाधित रहती हैं। इन व्यवहारिक स्थितियों से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार जिस तरह के सुधारों की वकालत कर रही है उसके लिये जमीन तैयार ही नही है।

नोटबंदी को लेकर जो दावा आरबीआई ने 99% पुराने नोट वापिस आने का किया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि देश के भीतर कालेधन के आंकड़ो को लेकर स्वामी रामदेव जैसे जो लोग दावे कर रहे थे या तो वह आंकडे गल्त थे उनकी सूचना और आंकलन गल्त था या फिर सरकार नोटबंदी के बावजूद कालेधन को पकड़ने में पूरी तरह असफल रही है। यदि सरकार असफल नही है तो क्या जो एक प्रतिशत पुराने नोट वापिस नही आये हैं वह कालाधन है। इस पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

आज सरकार बैंकिंग सुधारों को बैंक युनियनों ने ही जन विरोधी करार दिया है। यूनियनों ने पब्लिक सैक्टर बैंको के निजिकरण और बैंको के विलय का विरोध किया है। आज करीब 6 लाख करोड़ का एनपीए चल रहा है और इसमें 70% से अधिक बड़े कॉरपोरेट घरानो का है। लेकिन इन लोगों के खिलाफ कारवाई करने की बजाये सरकार इन्हे किसी न किसी रूप में पैकेज देकर लाभ पहुंचा रही है। बल्कि नोटबंदी के दौरान हर व्यक्ति को 500 और 1000 के नोटों की शक्ल में रखी अपनी संचित पूंजी को जबरन बैंको में ले जाकर जमा करवना पड़ा और फिर कई दिनों तक उसे उतनी निकासी करने की सुविधा नही मिली तो इस तरह अचानक बैंकों के पास भारी भरकम पैसा आ गया तो क्या इस पैसे का अपरोक्ष में लाभ इन कॉरपोरेट घरानों को नही मिला? क्योंकि बैंकों ने इस पैसे का निवेश इन घरानों के अतिरिक्त और कहीं तो किया नही। बल्कि बैंकों के पास इतना डिपोजिट आ जाने के बाद तो बैंको ने बचत पर ब्याज दरें तक कम कर दी। इस तरह सरकार के नोटबंदी से लेकर बैंकिंग सुधारों तक के सारे फैसलों से आम आदमी को कोई लाभ नही मिल पा रहा है। क्योंकि आम आदमी के लिये यह सारे सुधारवादी फैसले तभी लाभदायक सिद्ध होंगे जब मंहगाई और बेरोजगारी पर लगाम लगेगी और इसकी कोई संभावना नजर नही आ रही है।

बेमौसमी सब्जी उत्पादन से ग्रामीण आर्थिकी का कायाकल्प

प्रदेश सरकार ने कृषक समुदाय को परम्परागत फसलों के बजाए नकदी फसलों को उगाने के प्रति प्रेरित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना आरम्भ की है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक लोकप्रिय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक कृषक समुदाय नकदी फसलें, विशेषकर बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए आगे आएं।

हिमाचल प्रदेश पहले ही देशभर में 'फल राज्य' के रूप में जाना जाता है और अब राज्य तेजी से बेमौसमी–सब्जी उत्पादन में एक अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। कृषक समुदाय बेमौसमी सब्जी उत्पादन को बड़े पैमाने पर अपना रहा है और राज्य में सब्जी उत्पादन कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों से लेकर 4000 मीटर ऊंचाई तक वाले क्षेत्रों में किया जाने लगा है जिससे वर्ष भर यहां सब्जी उत्पादन संभव हो पाया है। इसी विशेषता के कारण यह प्रदेश अब सब्जी उत्पादन में देश का एक 'प्राकृतिक ग्लास हाऊस' के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।

सदियों से अनाज की परम्परागत फसलों पर बल दिया जाता रहा है ताकि सबको भरपेट अन्न उपलब्ध हो सके। लेकिन प्रदेश सरकार तथा कृषि विभाग द्वारा किसानों को उपदान दरों पर सामग्री उपलब्ध करवाकर संयुक्त प्रयासों से सब्जी उत्पादन एक कमाऊ नकदी फसल के रूप में बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है।

प्रदेश में कृषि–अनुकूल जलवायु है तथा बेमौसमी–सब्जियों के उत्पादन की यहां अपार संभावनाएं हैं। इन सब्जियों में मटर, टमाटर, शिमला मिर्च, फ्रांसबीन, पत्तागोभी, फूलगोभी तथा खीरा इत्यादि शामिल हैं जो यहां ऐसे समय में बड़े पैमाने पर उगाई जा रही हैं जब ये सब्जियां मैदानी क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं होती हैं। यही कारण है कि किसानों को यहां उगाई जा रही बेमौसमी–सब्जियों के अच्छे दाम कृषकों को मिल रहे हैं जो परम्परागत फसलों से नहीं मिल पाते हैं।

आज प्रदेश में 77,000 हैक्टेयर भूमि सब्जी उत्पादन के अधीन है जिस पर लगभग 16.54 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन किया जा रहा है जबकि वर्ष 2000–01 के दौरान केवल 5.80 लाख मीट्रिक टन था। सब्जी उत्पादकों को बेमौसमी–सब्जी उत्पादन से 60 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये प्रति हैक्टेयर लाभ हो रहा है जबकि पारम्परिक फसलों से यह लाभ केवल 8 हजार रुपये से लेकर 10 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर ही हो पाता है।

प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, जैविक खेती तथा संरक्षित खेती को लोकप्रिय बनाने पर भी बल दिया जा रहा है ताकि कृषि क्षेत्र विशेषकर सब्जी उत्पादन में यह प्रदेश तेजी से आगे बढ़े। इस दिशा में कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। 'डॉ. वाई.एस. परमार किसान स्वरोजगार योजना' के अंतर्गत 5.50 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में 3050 पॉलीहाऊस स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार कृषि उत्पादन की गुणवत्ता में बढ़ौतरी के लिए प्रदेश में जैविक खेती को अपनाने के लिए 40 हजार किसान आगे आए हैं और यह एक प्रशंसनीय पहल है।

प्रदेश का अधिकतर कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर होने के कारण राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा के अंतर्गत लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 321 करोड़ रुपये की 'फसल विविधिकरण संवर्द्धन परियोजना' के सफल कार्यान्वयन से इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को बड़ा बल मिला है तथा इस परियोजना से 945 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधा के तहत लाया जा सका है। 'राजीव गांधी सूक्ष्म सिंचाई योजना' के अंतर्गत भी लगभग 1300 हैक्टेयर कमांड क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान की गई है।

किसानों को बेहतर पौध सामग्री तथा उच्च किस्म के सब्जी बीज उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत जिला शिमला के जुब्बड़हट्टी में सब्जी नर्सरी उत्पादन के लिए एक 'उत्कृष्ट केन्द्र' स्थापित किया गया है। ऐसे ही दो और केन्द्र जिला सोलन व मण्डी में भी स्थापित किए जा रहे हैं।

राज्य के मेहनतकश कृषक समुदाय तथा प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान करने की सकारात्मक सोच के परिणामस्वरूप फसलों के विविधीकरण की दिशा में प्रशंसनीय कार्य से प्रदेश की ग्रामीण आर्थिकी का कायाकल्प हुआ है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में लगभग 62 प्रतिशत लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिल रहा है तथा यह क्षेत्र प्रदेश की कुल राज्य घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत का योगदान भी कर रहा है।

प्रदेश सरकार ने कृषक समुदाय को परम्परागत फसलों के बजाए नकदी फसलों को उगाने के प्रति प्रेरित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना आरम्भ की है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक लोकप्रिय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक कृषक समुदाय नकदी फसलें, विशेषकर बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए आगे आएं।

हिमाचल प्रदेश पहले ही देशभर में 'फल राज्य' के रूप में जाना जाता है और अब राज्य तेजी से बेमौसमी–सब्जी उत्पादन में एक अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है। कृषक समुदाय बेमौसमी सब्जी उत्पादन को बड़े पैमाने पर अपना रहा है और राज्य में सब्जी उत्पादन कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों से लेकर 4000 मीटर ऊंचाई तक वाले क्षेत्रों में किया जाने लगा है जिससे वर्ष भर यहां सब्जी उत्पादन संभव हो पाया है। इसी विशेषता के कारण यह प्रदेश अब सब्जी उत्पादन में देश का एक 'प्राकृतिक ग्लास हाऊस' के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।

सदियों से अनाज की परम्परागत फसलों पर बल दिया जाता रहा है ताकि सबको भरपेट अन्न उपलब्ध हो सके। लेकिन प्रदेश सरकार तथा कृषि विभाग द्वारा किसानों को उपदान दरों पर सामग्री उपलब्ध करवाकर संयुक्त प्रयासों से सब्जी उत्पादन एक कमाऊ नकदी फसल के रूप में बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है।

प्रदेश में कृषि–अनुकूल जलवायु है तथा बेमौसमी–सब्जियों के उत्पादन की यहां अपार संभावनाएं हैं। इन सब्जियों में मटर, टमाटर, शिमला मिर्च, फ्रांसबीन, पत्तागोभी, फूलगोभी तथा खीरा इत्यादि शामिल हैं जो यहां ऐसे समय में बड़े पैमाने पर उगाई जा रही हैं जब ये सब्जियां मैदानी क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं होती हैं। यही कारण है कि किसानों को यहां उगाई जा रही बेमौसमी–सब्जियों के अच्छे दाम कृषकों मिल रहे हैं जो परम्परागत फसलों से नहीं मिल पाते हैं।

आज प्रदेश में 77,000 हैक्टेयर भूमि सब्जी उत्पादन के अधीन है जिसपर लगभग 16.54 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन किया जा रहा है जबकि वर्ष 2000–01 के दौरान केवल 5.80 लाख मीट्रिक टन था। सब्जी उत्पादकों को बेमौसमी–सब्जी उत्पादन से 60 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये प्रति हैक्टेयर शुद्ध लाभ हो रहा है जबकि पारम्परिक फसलों से यह लाभ केवल 8 हजार रुपये से लेकर 10 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर ही हो पाता है।

प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, जैविक खेती तथा संरक्षित खेती को लोकप्रिय बनाने पर भी बल दिया जा रहा है ताकि कृषि क्षेत्र विशेषकर सब्जी उत्पादन में यह प्रदेश तेजी से आगे बढ़े। इस दिशा में कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। 'डॉ. वाई.एस. परमार किसान स्वरोजगार योजना' के अंतर्गत 5.50 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में 3050 पॉलीहाऊस स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार कृषि उत्पादन की गुणवत्ता में बढ़ौतरी के लिए प्रदेश में जैविक खेती को अपनाने के लिए 40 हजार किसान आगे आए हैं और यह एक प्रशंसनीय पहल है।

प्रदेश का अधिकतर कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर होने के कारण राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा के अंतर्गत लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 321 करोड़ रुपये की 'फसल विविधिकरण संवर्द्धन परियोजना' के सफल कार्यान्वयन से इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को बड़ा बल मिला है तथा इस परियोजना से 945 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधा के तहत लाया जा सका है। 'राजीव गांधी सूक्ष्म सिंचाई योजना' के अंतर्गत भी लगभग 1300 हैक्टेयर कमांड क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान की गई है।

किसानों को बेहतर पौध सामग्री तथा उच्च किस्म के सब्जी बीज उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत जिला शिमला के जुब्बड़हट्टी में सब्जी नर्सरी उत्पादन के लिए एक 'उत्कृष्ट केन्द्र' स्थापित किया गया है। ऐसे ही दो और केन्द्र जिला सोलन व मण्डी में भी स्थापित किए जा रहे हैं।

राज्य के मेहनतकश कृषक समुदाय तथा प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान करने की सकारात्मक सोच के परिणामस्वरूप फसलों के विविधीकरण की दिशा में प्रशंसनीय कार्य से प्रदेश की ग्रामीण आर्थिकी का कायाकल्प हुआ है। प्रदेश में कृषि क्षेत्र में लगभग 62 प्रतिशत लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिल रहा है तथा यह क्षेत्र प्रदेश की कुल राज्य घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत का योगदान भी कर रहा है।

पर्यटन से भारत की विदेशी मुद्रा आय में 32 प्रतिशत वृद्धि

* ओ.पी.शर्मा

अन्य क्षेत्रों में तेजी से हो रही प्रगति के साथ-साथ भारतीय पर्यटन क्षेत्र भी अब निश्चत रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा है। ''अतुल्य भारत'' के रूप में वर्णित अनेक तीर्थ स्थलों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ हमारा देश धीरे-धीरे प्राकृतिक सौन्दर्य वाले अनेक स्थानों, विशिष्ट वातावरण और अनेकअन्य आकर्षणों के साथ लोकप्रियता हासिल कर रहा है। इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। हमारा देश वैश्विक पर्यटन उद्योग में अपनी उचित हिस्सेदारी और स्थिति को और मजबूत कर रहा है।

हाल के वर्षों में सामाजिक एकता और आर्थिक विकास के प्रमुख चालक के रूप में पर्यटन प्रमुखता से आगे बढ़ रहा है। तीर्थयात्रा, व्यापार और अनेक अन्य कारणों से यात्रा करना प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। जहां आजादी के समय केवल 17,000 पर्यटक ही देश में आए थे वहीं वर्तमान में पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। लेकिन उच्च संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, भारत के पर्यटन उद्योग को और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार द्वारा किए गए कुछ शानदार प्रयासों और प्रचार योजनाओं के कारण यह क्षेत्र निश्चित रूप से वैश्विक पर्यटन क्षेत्र में अपना उचित स्थान तैयार करेगा।

आजादी के बाद से पर्यटन के महत्व को ध्यान में रखते हुए ठोस नीतियों और विस्तृत योजनाओं को अलग-अलग चरणों में लागू किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पर्यटन व्यापार में लगातार वृद्धि और विकास हुआ है। वैश्विक भ्रमण और पर्यटन क्षेत्रों में अधिक गति लाने के लिए और अधिक से अधिक निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।

नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि 2016 में पर्यटन ने देश के सकल घरेलू उत्पाद में 14.02 लाख करोड़ (220 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का योगदान दिया और इसमें 9.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पर्यटन के कारण 40. 343 मिलियन नौकरियां सृजित हुई जो अपने कुल रोजगार का 9.3 प्रतिशत है। 6.8 प्रतिशत की वार्षिक गति से बढ़ने के साथ इस क्षेत्र के 2027 तक 28.49 लाख करोड़ (440 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुंचने की उम्मीद है जो हमारी जीडीपी का 10 प्रतिशत है। एक उदाहरण के तौर पर देखें तो भारत के मेडिकल पर्यटन का अनुमानित आंकड़ा 3 बिलियन अमरीकी डॉलर है और 2020 तक यह बढ़कर 7-8 अरब डॉलर होने का अनुमान है। 2014 में लगभग 184,300 विदेशी मरीजों ने चिकित्सा उपचार के लिए भारत की यात्रा की। 2016 में 88.90 लाख विदेशी पर्यटक भारत आये, जबकि इससे पिछले वर्ष यह आंकड़ा 80.27 लाख था जिसमें 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 2012 में घरेलू पर्यटकों की संख्या लगभग 1,036.35 मिलियन थी, जिसमें वर्ष 2011 की तुलना में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तीर्थ पर्यटन की संख्या में भी हर साल लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने में युवा शक्ति की भागीदारी की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

वैश्विक यात्रा और पर्यटन पर विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व के 136 देशों में भारत का 40वां स्थान है। मौजूदा सरकार द्वारा सड़कों के नेटवर्क, उच्च गति वाले रेल और हवाई सेवाओं, शानदार होटल की सुविधा, व्यावसायिक अवसरों, नकद रहित भुगतान प्रणाली, स्वच्छ वातावरण और उदारवादी वीजा व्यवस्था तथा उपयुक्त मानव संसाधनों में किए जा रहे सुधारों से पर्यटन के क्षेत्र का आंकड़ा तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।

निरंतर विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय और सभी राज्यों को भागीदारों के रूप में सही तरीके से तैयार की गई राष्ट्रीय नीतियों और योजनाओं पर कार्य करना होगा। वीजा नीति को उदार बना दिया गया है और ''अतुल्य भारत'' के विश्वव्यापी अभियान के उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र को और प्रोत्साहन देने और वैश्विक पर्यटक के आवागमन में भारत का दर्जा और बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। ई-टूरिस्ट वीजा सुविधा का विस्तार 150 से अधिक देशों तक किया जा चुका है तथा घरेलू और विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में अन्य योजनाओं के साथ उड़ान योजना भी काफी लंबा सफर तय करेगी।

देश में सभी प्रकार के पर्यटकों के अनुरूप अच्छी तरह से डिजाइन किए गए यात्रा पैकेज और पर्यटन और तीर्थ यात्रा सर्किट मौजूद हैं। सेवा क्षेत्र के बीच भारतीय पर्यटन और होटल उद्योग विकास का प्रमुख चालक हैं। पर्यटन देश के लिए विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत होने के साथ-साथ रोजगार मुहैया कराने का भी प्रमुख स्त्रोत है। प्रत्येक नागरिक को ''अतिथि देवो भव:'' (हर पर्यटक हमारा सम्मानित अतिथि है) की भावना का पालन करना होगा और ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन के स्वैच्छिक राजदूत के रूप में कार्य करना होगा।

भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग और खर्च करने की अतिरिक्त क्षमता में बढ़ोतरी से घरेलू और विदेशी पर्यटन के विकास को लगातार मदद मिल रही है। 2016 में घरेलू पर्यटकों के आगमन (डीटीवी) का आंकड़ा 15.5 फीसदी वर्ष दर वर्ष बढ़कर करीब 1.65 बिलियन हो गया। विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है और पर्यटन के माध्यम से भारत की विदेशी मुद्रा आय (एफईई) में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और अप्रैल, 2017 में यह 2.278 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 2030 तक भारत वैश्विक स्तर पर व्यापार से संबधित शीर्ष पांच बाजारों में स्थान बना लेगा क्योंकि देश में व्यवसायिक यात्रा खर्च 2015 के 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2030 तक तीन गुना होने की उम्मीद है। भारत के विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) में पिछले तीन वर्षो के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह संख्या अप्रैल, 2017 में 7.40 लाख थी जो अप्रैल 2016 में 5.99 लाख और अप्रैल 2015 में 5. 42 लाख थी। भारत यात्रा करने वाले अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई) की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है।

2017-18 के आम बजट में पर्यटन और अतिथि सत्कार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए, जिनमें पांच पर्यटन जोन की स्थापना, विशेष तीर्थाटन या पर्यटन ट्रेन तथा अतुल्य भारत अभियान की वैश्विक स्तर पर शुरूआत आदि शामिल है।

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और राज्य सरकारें, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और प्रत्येक नागरिक को देश के पर्यटन में योगदान देने के लिए संयुक्त रूप से हर संभव प्रयास करने चाहिए और भारत को वैश्विक पर्यटन हब बनाने के लिए अधिक से अधिक पहलों की शुरूआत करनी चाहिए।

डिजीटल क्रांति से देश में शासन और प्रशासन का डिजीटलीकरण

*डा. गुरमीत सिंह

प्रौद्योगिकी का विकास प्रगति की आधारशिला है और शताब्दियों में इसने समाज के कामकाज के तौर-तरीकों को बदला है। प्रौद्योगिकीय आविष्कारों ने मानव श्रम को कम करके, दक्षता लाकर और उत्पादकता बढ़ाकर समाज के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति ला दी है। चाहे शिक्षा में सूचना संचार प्रौद्योगिकी हो, मीडिया और सेवा क्षेत्र में डिजीटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा के लिए स्वचालित उपकरण क्यों न हो, समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रौद्योगिकी का लाभ मिल रहा है। भारत जैसे देश के लिए जहां परम्परागत धरोहरों का अचूक मिश्रण है और जो सबसे बड़ी 'युवा आबादी' के साथ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहां प्रौद्योगिकी क्रांति के साथ समाज का चेहरा बदलने के विशाल अवसर हैं। हांलाकि देश ने आजादी के बाद अनेक दशकों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय अविष्कारों को लागू होते हुए देखा है, वर्तमान सरकार ने न केवल देश में डिजीटल क्रांति की प्रकिया में तेजी लाने के लिए उत्प्रेरक का काम किया है बल्कि देश में डिजीटल विभाजन में सेतु बन्धन का काम किया है। पिछले तीन वर्षो में न केवल डिजीटल प्रौद्योगिकी के अन्वेषण, कार्यान्वयन और उपयोग में तेजी से वृद्धि देखने को मिली है बल्कि डिजीटलीकरण और उसके लाभों को निचले स्तर तक ले जाने और खासतौर से समाज के उन वर्गो तक पहुंचाने पर जोर दिया है जिन्हें कम विशेष अधिकार प्राप्त हैं।

भारत में डिजीटल क्रांति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने समाज के लगभग सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कायापलट की है। वर्तमान सरकार की डिजीटल इंडिया पहल के साथ शासन प्रणाली से लेकर बेहतर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सेवाओं में डिजीटलीकरण, कौशलैस अर्थव्यवस्था और डिजीटल लेन-देन, अधिकारी तंत्र में पारदर्शिता, कल्याणकारी योजनाओं का निष्पक्ष और तेजी से वितरण जैसे लक्ष्य प्राप्त होते दिखाई दिए हैं। पिछले तीन वर्षो में विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की पहलों पर अगर नजर डाली जाए तो पता लगता है कि किस प्रकार से भारत में डिजीटल क्रांति ने न केवल समाज के कामकाज के तौर तरीकों को बदला है बल्कि देश के साधन सम्पन्न लोगों और वंचितों के बीच की खाई को पाट दिया है।

किसी भी समाज में शिक्षा की गुणवत्ता समाज की वास्तविक रचना

की आधारशिला है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए, डिजीटल इंडिया की पहल ने समाज में शिक्षा के प्रसार में सुधार के लिए अनेक डिजीटल सेवाओं को एक साथ ला दिया है। चाहे प्राइमरी स्तर हो, सैकंडरी स्तर अथवा उच्च शिक्षा और अनुसंधान की सुविधा हो, इस क्षेत्र में विभिन्न डिजीटल योजनाएं देश की शिक्षा प्रणाली में क्रांति ला रही हैं। हांलाकि शिक्षा क्षेत्र में अनेक योजनाएं हैं, लेकिन कुछ का जिक्र किया जा सकता है- 'स्वयंम' योजना नौवीं कक्षा से लेकर स्नातक स्तर के छात्रों की कहीं भी किसी भी समय कक्षा में पढ़ाए गए पाठयक्रमों तक पहुंच बनाती है। इस डिजीटल योजना ने न केवल शिक्षा को अनेक छात्रों के दरवाजे तक ला दिया है। इसका उद्देश्य डिजीटल विभाजन को भी पाटना है क्योंकि जिन छात्रों की मुख्य धारा अथवा औपचारिक शिक्षा तक पहुंच नहीं है वे इस एप्लीकेशन तक पहुंच सकते हैं। एक अन्य डिजीटल योजना 'ई-पाठशाला' है जिसने वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिये शिक्षा की विषय वस्तु का प्रचार किया है। अगली पंक्ति में 'मिड डे मील निगरान ऐप', 'शाला सिद्धी' और ' शाला दर्पण' हैं जो स्कूल प्रशासन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हैं और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूलों और केन्द्रीय विद्यालयों का मूल्यांकन करते हैं। अनुसंधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए 'ओलैब' डिजीटल योजना है। ओलैब यानी स्कूल प्रयोगशाला प्रयोगों के लिए ऑनलाईन प्रयोगशाला छात्रों के लिए इंटरनेट पर प्रयोग कराना आसान बनाती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के पास 'राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल', 'ई ग्रंथालय', 'राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क' आदि हैं। ये डिजीटल पहल न केवल शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की तरफ देख रही हैं बल्कि वंचितों तक शिक्षा पहुंचा रही है जिससे डिजीटल क्रांति का इस्तेमाल समाज के सम्पन्न और वंचितों के बीच की खाई को कम करने के लिए किया जा रहा है।

शिक्षा का क्षेत्र समाज की रचना का निर्माण करता है, स्वास्थ्य सेवा भी समाज के लिए एक उतना ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसका सुरक्षित और स्थिर भविष्य है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार की विभिन्न डिजीटल पहल में शामिल हैं- 'डिजीटल एम्स' एक ऐसी परियोजना जिसका उद्देश्य यूआईडीएआई और एम्स के बीच प्रभावी सम्पर्क बनानाय 'ई-अस्पताल' योजना जो स्वास्थ्य प्रबंधन योजना का एक खुला स्त्रोत है। 'एमरक्तकोष'- एक वैब आधारित तंत्र जो सभी सरकारी ब्लड बैंकों को एक नेटवर्क से जोड़ देता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के अलावा वर्तमान सरकार ने शासन प्रणाली के डिजीटलीकरण के लिए विभिन्न पहलें की हैं। उदाहरण के लिए 'उमंग' का उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं, 'ई-पंचायत', 'ई-जिले', ई-कार्यालय के लिए एक ही जगह पर समाधान देना है। ये कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो देश में शासन और प्रशासन का डिजीटलीकरण कर रही हैं। इनके अलावा 'राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल' और 'ईसीआई-ईवीएम ट्रैकिंग सेवा भी शासन में पारदर्शिता लाने के लिए है। आधार योजना और भीम ऐप ने भी अर्थव्यवस्था के डिजीटलीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत की विशेषता कृषि क्षेत्र है। सरकार की डिजीटल इंडिया पहल किसानों की अनेक योजनाओं के लिए लाभकारी साबित हो रही है। कृषि क्षेत्र की कुछ योजनाओं में शामिल हैं, 'एम किसान', 'किसान पोर्टल', 'किसान सुविधा ऐप', 'पूसा कृषि', 'सॉयल हैल्थ कार्ड ऐप', 'ईनाम', 'फसल बीमा मोबाइल ऐप', 'एग्री मार्केट ऐप' और 'फर्टिलाइजर मॉनीटरिंग ऐप'। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 'निर्भय ऐप' और 'हिम्मत ऐप' जैसे एप्लीकेशन शुरू किए गए जिनका इस्तेमाल महिलाएं विपत्ति में पड़ने पर कर सकती हैं। कानूनप्रवर्तन एजेंसियों, अदालतों और न्याय प्रणाली के लिए भी ऐप हैं।

अत: विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा की गई अनेक पहलें न केवल समाज में क्रांति लाने का एक प्रयास है बल्कि शोषितों को ऊपर उठाने के लिए डिजीटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर देना है ताकि विभिन्न सामाजिक स्तरों के बीच अंतर को खत्म किया जा सके।

न्याय दिलाने के जनहित याचिकाओं की भूमिका महत्वपूर्णः न्यायमूर्ति लोकुर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में हि.प्र. राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं' पर व्याख्यान की श्रृंखला पर 4वें व्याख्यान का आयोजन

किया गया। इस समारोह का शुभारम्भ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी की उपस्थिति में किया।

अपने उद्घाटन सम्बोधन में न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा की जा रही व्याख्यान श्रृंखला पर प्रसन्नता जाहिर की। संविधान में दिए गए सामाजिक व आर्थिक न्याय विषय पर कहा कि न्यायपालिका समाज के सबसे कमजोर वर्गो को जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि कई बार स्थापित कानूनों का निर्वहन नहीं हो पाता और कुछ मामलों में कोई भी कानून नहीं होता है। इन दोनों मामलों में न्यायालय का यह दायित्व बनता है कि आम आदमी को न्याय दिलाए। उन्होंने कहा कि जनहित याचिकाओं ने सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के माध्यम से कैदियों, समाज के कमजोर वर्गो, महिलाओं व बच्चों इत्यादि के अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

न्यायिक सक्रियता पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आम लोगों को न्याय दिलाने में न्यायिक सक्रियता आवश्यक है, परन्तु वह अपनी सीमा में ही होनी चाहिए। उन्होंने समाज में सामाजिक तथा आर्थिक न्याय पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्र की 60 प्रतिशत सम्पदा मात्र एक प्रतिशत जनसंख्या के पास है, जबकि राष्ट्र की 40 प्रतिशत सम्पदा 99 प्रतिशत जनसंख्या के पास है। उन्होंने कहा कि नीति निर्माताओं व अर्थशास्त्रियों को लोगों को आर्थिक न्याय दिलाने के लिए समाधानों के साथ आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी क्षेत्र में अन्याय होता है तो न्यायपालिका को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और ऐसे में एसे मूक दर्शक बन कर नहीं रहना चाहिए।

इस अवसर पर न्यायमूर्ति लोकुर ने 16 मध्यस्थों, हि.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ जुड़े अधिवक्ताओं, को भी बधाई दी।

न्यायमूर्ति लोकुर ने हि.प्र. राज्य विधिक प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के गरीबों तथा जरूरतमंदों को न्याय उपलब्ध करवाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने हि.प्र. राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की लोक अदालतें, पूर्व अभियोग कार्यक्रम व वृक्षारोपण आदि कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सराहना की। उन्होंने हि. प्र. राज्य उच्च न्यायालय की परिधि में मेडिटेशन केन्द्र का भी शुभारम्भ किया।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल ने मुख्य अतिथि तथा अन्य का स्वागत करते हुए कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसके पास सबसे बड़ा संविधान है। उन्होंने कहा कि राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण प्रदेश भर में पौधरोपण आयोजित कर रहा है तथा इसमें छठीं कक्षा से ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आम लोगों को तीव्र न्याय उपलब्ध करवाने के लिए पूर्व अभियोग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रथम सितम्बर, 2017 को उच्च न्यायालयों में पूर्व अभियोग मेडिटेशन अदालत आयोजित की गई, जिसमें 12 व 13 अगस्त, 2017 को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में दुर्घटना के दौरान 45 मृतकों के दावों को निपटारा करने के लिए आयोजित की गई। इनमें 16 दावों का निपटारा किया गया और एक करोड़ 54 लाख 85 सौ रुपये की राशि वितरित की गई।

हि.प्र. विधिक सेवाएं प्राधिकरण के प्रशासनिक अधिकारी यशवंत सिंह चोगल ने इस अवसर पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान, न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर, न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल, न्यायमूर्ति संदीप शर्मा, न्यायमूर्ति चन्द्रभूषण बरोवालिया, सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.के. महाजन, ए.के. गोयल, कुलदीप सिंह कंवर, पी.एस. राणा तथा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कर्मचारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी देवी–देवताओं के नजराने में

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अन्तर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में भाग लेने वाले देवी–देवताओं के नजराने में पांच प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है और 'श्रीखंड महोदव' यात्रा के लिए कुल्लू दशहरा की निधि से 10 लाख रुपये जारी करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री 30 सितम्बर, 2017 से आरम्भ होने वाले सप्ताह भर चलने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के आयोजन के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि कुल्लू दशहरा राज्य के लोगों के लिए महत्वपूर्ण आयोजन है और यह सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए कि इसकी सांस्कृतिक विरासत यथावत बनी रहे। उन्होंने कला केन्द्र में दिन के समय गांवों के अन्दर सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं शुरू करवाने के भी निर्देश दिए ताकि जिला के दूरवर्ती क्षेत्रों से आए लोगों का भरपूर मनोरंजन हो सके।

मुख्यमंत्री ने बड़े पैमाने पर ग्रामीण खेल गतिविधियां आयोजित करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि राज्य के बाहर से आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कलाकारों तथा सांस्कृतिक दलों की समुचित देख–भाल की जानी चाहिए तथा किसी भी स्थिति में कानून व व्यवस्था को बनाए रखा जाना चाहिए।

कुल्लू के उपायुक्त युनूस खान ने कहा कि सप्ताह भर चलने वाले दशहरा महोत्सव में भाग लेने के लिए लगभग 305 स्थानीय देवी–देवताओं को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने व्यय तथा बचत के लेखे–जोखे का विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि दशहरा समिति के आग्रह पर रूस से सांस्कृतिक दल ने उत्सव में भाग लेने के अलावा आईसीसीआर नई दिल्ली के तीन अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक दलों के लिए सहमत हुई है। उन्होंने कहा कि समिति ने श्रीलंका, मध्यपूर्व तथा लेटिन अमेरिका से सांस्कृतिक दलों के लिए आग्रह किया है।

उन्होंने स्थानीय कलाकारों की उपयुक्त स्क्रीनिंग करने और प्रस्तुति के दौरान पारम्परिक परिधानों का प्रयोग सुनिश्चित बनाने का आश्वासन दिया।

मुख्य सचिव वी.सी. फारका ने पर्यटन विभाग से भी पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

पत्रकारों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार सदैव तत्परः मुकेश अग्निहोत्री

शिमला/शैल। उद्योग और सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत पत्रकारों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार सदैव तत्पर रही है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में विभिन्न जिलों में प्रेस क्लबों की स्थापना को विशेष प्राथकिता दी है ताकि पत्रकारों को अपना कार्य करने के लिए बेहतर सुविधा मिल सके।

अग्निहोत्री ऊना दिवस के अवसर पर हरोली उपमंडल स्तर के लिए टाहलीवाल में 27 लाख रुपये की लागत से स्थापित किए गए प्रेस क्लब का लोकार्पण करने के अवसर पर संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रेस क्लबों की स्थापना अथवा सुधार के लिए 2.45 करोड़ रुपये जारी किए हैं। शिमला, हमीरपुर, सोलन, नाहन, जोगिन्द्रनगर, नेरचौक और घुमारवीं में प्रेस क्लबों के नए भवन निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है। विभिन्न प्रेस क्लबों में फर्नीचर व कम्प्यूटर आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए 40.21 लाख रूपये खर्च किए गए।

मंत्री ने कहा शिमला में स्थापित राज्य स्तरीय प्रेस क्लब के जीर्णोद्धार और कंप्यूटर व टीवी सुविधा प्रदान करने के लिए 14.88 लाख रुपये जारी किए गए। ऊना में प्रेस क्लब भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। धर्मशाला में भी प्रेस क्लब भवन बनाया जाएगा जिसके लिए 15 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

नाहन में प्रेस क्लब भवन के निर्माण का कार्य आरम्भ किया गया है जिसके लिए अभी तक 26.18 लाख रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है। बिलासपुर प्रेस क्लब में फर्नीचर व कंप्यूटर सुविधा के लिए धनराशि दी गई है। मंडी में प्रेस क्लब के लिए 8 लाख रुपये जबकि केलंग में प्रेस क्लब में फर्नीचर व कंप्यूटर जैसी सुविधाओं के लिए 6.83 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं।

अग्निहोत्री ने कहा कि कुल्लू में प्रेस क्लब बनाने के लिए 25.94 लाख रुपये की स्वीकृति सरकार ने प्रदान की है जिस पर कार्य शीघ्र आरम्भ होगा। नगरोटा बगवां, बैजनाथ, पालमपुर, जयसिंहपुर, रामपुर बुशैहर, रोहडू में उप मंडल स्तरीय प्रेस क्लब भवन में सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक–एक लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। इसके अलावा नूरपुर प्रेस क्लब को दो लाख रुपये व मनाली प्रेस क्लब के लिए 1.50 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि कांगड़ा प्रेस क्लब का कार्य पूरा करने के लिए पांच लाख रुपये, हरोली में प्रेस क्लब भवन के निर्माण व अन्य सुविधाओं के लिए 25 लाख रुपये से अधिक की राशि प्रदान की गई है। सुंदरनगर में इस कार्य पर 10 लाख रुपये से अधिक व्यय किए गए हैं जबकि पांवटा साहिब में प्रेस क्लब का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसके लिए लगभग 19 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

नेशनल फ्रीडम पार्टी हिमाचल में 68 सीटों पर लड़ेगी चुनाव

शिमला/शैल। भाजपा से खफा हुए विवेकानंद फाऊडेशन दिल्ली ने नेशनल फ्रीडम पार्टी का गठन किया है, जो हिमाचल प्रदेश में अपना पहला चुनाव लडने जा रही है। फाऊडेशन के ट्रस्टी अमलान विश्वास ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव लडने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि पार्टी साफ व ईमानदार छवी के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेगी।

उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर सत्ता में आने के बाद दो राजधानियां बनाने का आरोप लगाया। इसमें एक राजधानी दिल्ली तथा दूसरी राजधानी नागपुर है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संघ चला रहा है केंद्र सरकार में मंत्री कौन बनेगा, इसका निर्णय संघ द्वारा लिया जाता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते थे, उनका भाजपा में आते ही शुद्धिकरण हो गया है। आज भाजपा के 84 सांसद ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस में थे। उन्होंने कहा कि आज देश में विपक्ष नहीं है तथा विपक्ष के बिना सरकार नहीं चल सकती है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति विशेष को खड़ा कर भाजपा को समाप्त कर दिया गया है। भाजपा ने चुनावों के समय जो वायदे किए थे, वह पूरे नहीं किए हैं। इसलिए नेशनल फ्रीडम पार्टी देश में 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। साथ ही हिमाचल में सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विवेकानंद फाऊडेशन का कोई भी पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ेगा। फाऊडेशन नेशनल फ्रीडम पार्टी को पूरा सहयोग करेगी। इस मौके पर भाजपा, हिलोपा व आम आदमी पार्टी छोड़ चुके पूर्व विधायक महेंद्र नाथ सोफत तथा देश बधूं सूद, हरीष गुलेरिया व अन्य लोग उपस्थित थे।

विवेकानंद फाऊडेशन के ट्रस्टी अमलान विश्वास ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिमी बंगाल से चुनाव लड़ने तथा उसे जीतने की चुनौती दी। विश्वास ने कहा कि वह स्वयं भी इस चुनाव में उतरेंगे तथा पीएम मोदी फिर जीत कर बताएं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के अच्छे दिन आने की बात पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जहां 20 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार हैं, वहां अच्छे दिन कैसे आएं हैं।

पूर्व विधायक महेंद्र नाथ सोफत ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस व भाजपा का तीसरा विकल्प लाकर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि सुखराम की हिमाचल विकास कांग्रेस तथा महेश्वर सिंह की हिलोपा के हालात देखने के बाद लोगों का विश्वास तीसरे विकल्प से हटा है। लेकिन वह अपने तीसरे विकल्प के संकल्प के लिए प्रयासरत्त हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नेताओं की महत्वकांक्षा के कारण तीसरा विकल्प नहीं उभर पाया। सुखराम ने पुत्रमोह में तथा महेश्वर सिंह ने अपनी महत्वकांक्षा में पार्टी का विलय कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सेवानिवृत अधिकारी सरकार को चला रहे हैं। हैरानी की बात है कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से लेकर निजी सचिव सेवानिवृत अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1998 से पहले प्रदेश शांतिप्रिय, इमानदारी व कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गुडिया कांड ने प्रदेश को शर्मसार किया है तथा इस मामले में 8 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सीबीआई ने हिरासत में लिया है, जो कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। इस मामले में पुलिस किस दबाव में काम कर रही है, लोगों के समक्ष सच्चाई आनी चाहिए। इसके अलावा प्रदेश में भाजपा की स्थिति भी कांग्रेस की तरह ही है। वहीं केंद्र की भाजपा सरकार कारपोरेट सरकार बन गई है तथा गुजरात की तिकड़ी सरकार को चला रही है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी और संदिग्धों के नार्को टैस्ट से मामला सुलझने के आसार बढ़े

शिमला/शैल। कोटखाई के गुड़िया गैंगरेप एवम् हत्या तथा इसी मामले के एक आरोपी सूरज की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के प्रकरण में सीबीआई हिमाचल पुलिस के आईजी समेत आठ अधिकारियों/कर्मचारियों को हिरासत में लेकर उन्हें पूछताछ के लिये दिल्ली ले गयी है। इन लोगों से पूछताछ के दौरान जो कुछ सामने आया है उसके बाद सीबीआई ने शिमला के तत्कालीन एसपी डी डब्ल्यू नेगी सहित तीन और अधिकारियों को इसी मामले में दिल्ली तलब कर लिया है। माना जा रहा है कि सीबीआई इन तीनों की भी कभी भी अधिकारिक गिरफ्तारी की घोषणा कर सकती है। पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी के साथ ही सीबीआई ने उन पांचो आरोपीयों का नार्को टैस्ट करवाने की भी अदालत से अनुमति हासिल कर ली है जिन्हे गुड़िया मामले में प्रदेश पुलिस की एसआईटी ने गिरफ्तार किया था।

स्मरणीय है कि इस मामले में जब मुख्यमन्त्री के अधिकारिक फेस बुक पेज पर चार लोगों के फोटो वायरल हुए थे और इसके साथ यह दावा किया गया था कि इस रेप और हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है लेकिन यह फोटो वायरल होने के साथ ही इन्हें कुछ ही समय बाद जब एसआईटी ने अधिकारिक तौर पर एक पत्रकार वार्ता करके इसमें छः लोगों को गिरफ्तार करने पर अपनी पीठ थपथपाई तब यह सामने आया कि एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किये गये छः लोगों में वह चार लोग नहीं है जिनके फोटो मुख्यमन्त्री के फेसबुक पेज पर लोड हुए थे। पुलिस जब इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नही दे पायी तब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हर जगह धरने प्रदर्शन होने शुरू हो गये और सरकार तथा पुलिस पर यह आरोप लगना शुरू हो गया कि असली गुनाहगारों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है तथा निर्दोष लोगों को फसाया जा रहा है, जैसे जैसे यह जनाक्रोश बढ़ता गया उसी अनुपात में सरकार दवाब में आती चली गयी। प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लेकर सरकार और पुलिस से जवाब तलब कर लिया। इस तरह जब सरकार पर जनाक्रोश का दवाब बढ़ा तो सरकार ने मामला सीबीआई को सौंपने का फैसला ले लिया। मुख्यमन्त्री ने स्वयं प्रधानमन्त्री को पत्र लिखा और गृहमन्त्री राजनाथ सिंह से बातचीत की। सरकार के फैंसले पर उच्च न्यायालय ने भी सीबीआई को निर्देश दे दिये कि वह इस मामले की जांच अपने हाथ में ले। उच्च न्यायालय इस मामले में चल रही जांच पर सीबीआई से लगातार स्टेटस रिपोर्ट भी तलब कर रहा है। उच्च न्यायालय की इसी निगरानी के परिणामस्वरूप अदालत ने डीजीपी समेत सारी एसआईटी को इसमें प्रतिवादी बनाते हुए सभी सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग शपथ पत्र ले लिये है और सीबीआई ने अदालत में एसआईटी के सदस्यों पर इस जांच में सहयोग न करने का आरोप भी लगाया है।

एसआईटी सदस्यों द्वारा शपथ पत्र सौंपने तथा सीबीआई द्वारा असहयोग का आरोप लगने के बाद ही यह गिरफ्तारीयों की कारवाई हुई है। यह गिरफ्तारीयां आरोपी सूरज की पुलिस कस्टडी में हुई

मौत के प्रकरण में हुई है। स्मरणीय है कि एसआईटी ने सूरज की मौत को दूसरे आरोपी राजू के साथ हुई कथित मारपीट में राजू के नाम लगा दिया था लेकिन राजू की मां और मृतक सूरज की पत्नी ममता ने एसआईटी के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था। अब सीबीआई की जांच में भी पुलिस की कहानी सत्यापित नही हुई है। शैल के पाठक जानते हैं कि इस प्रकरण पर जो जो सवाल हमने उठाये थे आज वही सवाल सीबीआई जांच के बिन्दु बने हैं। राजू द्वारा सूरज की हत्या करना किसी भी तर्क से गले नहीं उतरता है। सूरज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सूत्रों के मुताबिक सूरज को पुलिस ने इलैक्ट्रिक शॉक तक दिये हैं। पुलिस सूरज को टार्चर करके उससे क्या कबूल करवाना चाहती थी? किसके कहने पर उसे इतना टार्चर किया गया कि इसमें उसकी मौत ही हो गयी। इन सवालों के जवाब अब सीबीआई जांच में सामने आयेंगे लेकिन यह स्पष्ट है कि सूरज को टार्चर करके पुलिस सारा गुनाह उसी से कबूल करवाना चाहती थी अन्यथा इतने टार्चर की आवश्यकता ही नही थी। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सूरज को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नही थे। इससे यह भी सन्देह होता है कि सूरज से गुनाह कबूल करवाकर पुलिस किसी और को बचाना चाहती थी। पुलिस ऐसा क्यों कर रही थी इसके दो ही कारण हो सकते हैं कि यह सब या तो पैसे के लिये किया जा रहा था या फिर किसी के दवाब में। इसका खुलासा सीबीआई की रिपोर्ट से होगा और यही खुलासा गुड़िया के गुनाहगारों तक पहुंचने में अहम कड़ी होगा।

गुड़िया के मामले में जब पुलिस ने छः लोगों को गिरफ्तार किया था तब यह सामने आ चुका था कि गुड़िया चार तारीख को करीब 4:15 बजे स्कूल से निकली थी। गुड़िया का शव 6 तारीख को सुबह 7:30 बजे उसके मामा को मिला था। मामा ने ही पुलिस को सूचना दी और गुड़िया के माता-पिता को। 6 तारीख को ही एफआरआई दर्ज हुई और सात तारीख को शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में मौत का समय चार तारीख को ही 4 से 5 बजे कहा गया है। यहां पर यह स्वभाविक सवाल उठता है कि स्कूल से निकलने और रेप तथा हत्या हो जाने के बीच केवल एक घन्टे का समय है। क्या एक घन्टे में 6 लोग रेप करके हत्या को भी अंजाम दे पायेंगे? क्योंकि स्कूल के अध्यापकों और बच्चों के मुताबिक स्कूल से निकलने का समय तो यही 4 से 4:15 है ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठना चाहिये था। गुड़िया के माता-पिता ने न तो चार तारीख को और न ही पांच तारीख को पुलिस को गुड़िया के घर न आने की रिपोर्ट लिखवाई, आखिर क्यों? क्या उनके ऊपर कोई दवाब था? यह सवाल जांच के शुरू में उठने थे जिन्हें पुलिस ने नही उठाया क्यों? अब इन सारे सवालों का खुलासा सीबीआई रिपोर्ट में ही सामने आयेगा। जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा था अब उनका नार्को टैस्ट होने के बाद यह सामने आ जायेगा कि उन लोगों की इस अपराध में संलिप्तता है या नही। यदि नार्को में उनकी संलिप्तता न पायी गयी तो पुलिस की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं और इसकी गाज कुछ और लोगों पर भी गिरना तय है। क्योंकि फिर दो ही बिन्दु बचेंगे कि या तो इसमें पैसे का बड़ा खेल था या फिर कोई बड़ा दवाब था।

चुनाव लड़ना वीरभद्र की राजनीतिक आवश्यकता

शिमला/शैल। जहां सीबीआई जांच में यह मामला सुलझने के करीब पहुंचने लगा है उसी अनुपात में विपक्ष ने इस मामले में सरकार और मुख्मन्त्री के खिलाफ अपना हमला और तेज कर दिया है। सांसद

अनुराग ठाकुर ने तो सीधे मुख्मन्त्री की पत्नी और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह पर आरोप लगाया है कि वह इस मामले के दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। इस प्रकरण में अपने परिवार पर लगने वाले आरोपों से आहत होकर वीरभद्र ने ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाने वालों के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करने की चेतावनी दी है। लेकिन जहां सीबीआई जांच के बावजूद विपक्ष मुख्यमन्त्री के खिलाफ लगातार हमलावर होता जा रहा है वहीं पर कांग्रेस इस मुद्दे पर एकदम चुप्पी साध कर बैठ गयी है।

माना जा रहा है कि कांग्रेस की इसी खामोशी से आहत होकर वीरभद्र ने अब अगला विधानसभा चुनाव लड़ने और चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करने का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस समय वीरभद्र जिस तरह के हालात में घिरे हुए है उनको सामने रखते हुए यह चुनाव लड़ना उनकी राजनीतिक विवशता बन गयी है। क्योंकि सीबीआई और ईडी के जो मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं उन्हे अन्तिम फैसले तक पहुंचने में समय लगेगा और उसके लिये न केवल प्रदेश की सक्रिय राजनीति में रहना होगा बल्कि उन्हें इसमें पूरी तरह केन्द्रिय भूमिका में रहना आवश्यक है। इसी के साथ उन्हें अपने बेटे विक्रमादित्य को भी राजनीति में स्थापित करने के लिये विधानसभा में पहुंचाना होगा। इसको सुनिश्चित करने के लिये स्वयं चुनाव लड़ना और पार्टी का नेतृत्व अपने साथ रखना ही एक मात्र उपाय शेष है।

क्योंकि अभी ईडी ने महरोली स्थित फार्म हाउस की जो प्रोविजिनल अटैचमैन्ट इस वर्ष मार्च में की थी वह अब कनफर्म हो गयी है। इससे पहले ग्रेटर कैलाश की संपत्ति की भी अटैचमैन्ट स्थायी हो गयी है। अब इन सम्पतियों को छुड़ाने के लिये अदालत के अन्तिम फैसले तक इन्तजार करना होगा। जबकि इस धन शोधन के मामले में अभी तक वीरभद्र के खिलाफ जांच पूरी होकर चालान अदालत में दायर होना है और माना जा रहा है कि इसमें भी अभी और समय लग सकता है। ऐसे में यदि सबका समग्रता में आंकलन किया जाये तो स्पष्ट हो जाता है कि इस लड़ाई को लड़ने और जीतने के लिये सक्रिय राजनीति का हथियार अतिआवश्यक है और इसी के लिये चुनाव लड़ना राजनीतिक आवश्यकता है।

केन्द्रिय मन्त्रीमण्डल के विस्तार

.....पृष्ठ 1 का शेष

दिया कि अदालत को एक महिला के ब्यान की बजाये करोड़ो लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर फैसला देना चाहिये था। इन ब्यानों से भी आम आदमी आहत हुआ है। फिर पार्टी ने साक्षी महाराज के ब्यान से किनारा करने के अतिरिक्त उनके खिलाफ कोई कारवाई नही की। जबकि यहां कोटखाई के गुड़िया प्रकरण पर सरकार और मुख्यमन्त्री के खिलाफ भाजपा की आक्रामकता लगातार जारी है। पार्टी ने इसी प्रंसग में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग तक कर डाली है। हिमाचल के संद्धर्भ में पार्टी का स्टैण्ड पूरी तरह जायज है लेकिन इसी स्टैण्ड को सिरसा काण्ड से मिलकर देखा जायेगा तो फिर इसमें जरूरत से ज्यादा राजनीति किये जाने का आरोप लगना स्वभाविक है और भाजपा ने इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना डाला है बल्कि इस मुद्दे के साये में भ्रष्टाचार जैसे अन्य गंभीर मुद्दे पूरी तरह पीछे छोड़ दिये गये हैं। जबकि विश्लेषकों की नजर में सिरसा कांड के साये में इससे नुकसान होने की संभावना हो सकती है क्योंकि यह मामला आज की तारीख में सीबीआई के पास है और सीबीआई को सरकार ने ही भेजा है। यदि इसमें सरकार सीबीआई को भेजने के लिये तैयार नही होती और उच्च न्यायालय के आदेशों पर ही सीबीआई को भेजा जाता तब सरकार की नीयत पर शक किया जा सकता था, लेकिन इस समय शक करने को महज राजनीति के तौर पर ही देखा जायेगा और उससे भाजपा को ज्यादा लाभ नही मिलेगा।